

प्रेषक,

एस० रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, उत्तराखण्ड।
- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक:- 11, जनवरी, 2017

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट पिटिशन संख्या-140/2015 ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मातृ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition (PIL) संख्या 140/2015 श्री ललित मिगलानी बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य पर दिनांक 20.12.2016 द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं।

It is further directed that there shall be a total ban of sale, use and storage of plastic carry bags throughout the State of Uttarakhand w.e.f. 01.01.2017. No person shall be permitted to bring carry bags in the State of Uttarakhand by any means of transport, including the bus, trains and air. The State Government shall launch a special campaign to make the people aware to use paper or jute bags to save the environment.

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें :—

- सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के Plastic/Thermacol से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा।
- उक्त संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डों, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों में विज्ञप्ति, लाउड स्पीकर्स के द्वारा एवं नुक्कड़ बैठकों एवं नाटकों द्वारा आम जनता को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त करें।
- उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित से ₹5000/- का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

उक्त के अनुपालन हेतु नगरीय श्रेत्र से संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद् तथा वन श्रेत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी जिम्मेदार होंगे।


भवदीय,
Rama S. Ramaswamy

(एस० रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. N.I.C, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

M. Joshi
(मीनाक्षी जोशी)

अपर सचिव

9/1
h